Websites:
http://www.sciencepub.net/academia
http://www.sciencepub.net

Emails:
aarena@gmail.com
editor@sciencepub.net

Academia Arena

MARSLAND PRESS
Multidisciplinary Academic Journal Publisher

Study of the economic ideas of Professor Amartya Sen

प्रोफेसर अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों का अध्ययन

Dr. Shaiphali Jain

Assistant Professor (Economics) in Shri Prem Prakash Memorial College of Education (Teerthanker Mahaveer University), Moradabad, Uttar Pradesh, India.
Email: shaiphali1980jain@gmail.com

Abstract: His aim behind choosing economics as the subject of study was to fight poverty, so during the economic analysis, he paid full attention to understanding the economic and social needs of the lower person of the society and reviewing the causes of poverty. He developed the Poverty Index to reflect the state of income distribution. For this, while defining the relationship between income distribution, income inequality and purchasing power of the society in different income distributions, he defined the poverty index and other welfare indicators. This made it easy to understand and address the symptoms of poverty. According to Amartya Sen, no citizen of the welfare state feels neglected. According to Amartya Sen, no citizen of the welfare state feels neglected. In the course of his famine studies, he came to the shocking result that the democratic system has more capacity to deal with famine-like situations, because it is not possible for governments to ignore public problems due to accountability to the people. Giving the example of India, he clarified that there came many occasions after independence when food production was less than the requirement. In many places due to floods and other natural calamities, the crops suffered greatly, but the government did not allow famine-like conditions to occur by making the distribution systems tight.
[Jain, S. **Study of the economic ideas of Professor Amartya Sen**. *Academ Arena* 2021;13(1):66-75]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). http://www.sciencepub.net/academia. 7. doi:10.7537/marsaaj130121.07.

Keywords: Economic Ideas, Professor Amartya Sen

सारांश (Abstract): अर्थशास्त्र को अध्ययन का विषय चुनने के पीछे उनका उद्देश्य गरीबी से जूझना था, इसलिए अर्थशास्त्रीय विवेचना के दौरान उन्होंने समाज के निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया । उन्होंने आय वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक विकसित किया । इसके लिए आय वितरण, आय में असमानता और विभिन्न आय वितरणों में समाज की क्रय क्षमता के सम्बन्धों की सूक्ष्म व्याख्या करते हुए उन्होंने निर्धनता सूचकांक एवं अन्य कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया । इससे निर्धनता के लक्षणों को समझना एवं उनका निराकरण करना आसान हो गया । अमर्त्य सेन के अनुसार, कल्याणकारी राज्य का कोई भी नागरिक स्वयं को उपेक्षित महसूस नहीं करता । अकाल सम्बन्धी अपने अध्ययन के दौरान वे इस चौंकाने बाले परिणाम पर पहुँचे कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अकाल जैसी स्थितियों से निपटने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही के कारण सरकारों के लिए जनसमस्याओं की अनदेखी कर पाना सम्भव नहीं होता । भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ आजादी के बाद कई अवसर आए जब खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकता से कम रहा । कई स्थानों पर बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ, किन्तु सरकार ने वितरण व्यवस्थाओं को चुस्त बनाकर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी ।
कुंजी शब्द (Keywords): अमर्त्य सेन, शिक्षा, आर्थिक, विचार

प्रस्तावना (Introduction): अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिये 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं।अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पर्चे लिखे हैं। सन 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान

'भारत रत्न' से भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1970 के दशक से ही यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सन 2015 में ब्रिटेन के रॉयल अकैडमी ने उन्हें प्रथम 'चार्ल्सटन-इ.एफ.जी. जॉन मेनार्ड कीन्स पुरस्कार' से सम्मानित किया।

अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवम्बर, 1933 को कोलकाता के शांति निकेतन में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम आशुतोष सेन और माता का नाम अमिता सेन था। गुरु रविन्द्र नाथ टैगोर ने अमर्त्य का नामकरण किया था। अमर्त्य के पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे और सन 1945 में परिवार के साथ पश्चिम बंगाल चले गए और पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष) और फिर संघ लोक सेवा आयोग में कार्य किया। अमर्त्य की माता क्षिति मोहन सेन की पुत्री थीं, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जाने-माने विद्वान् थे और रविंद्रनाथ टैगोर के करीबी भी। अमर्त्य की प्रारंभिक शिक्षा सन 1940 में ढाका के सेंट ग्रेगरी स्कूल से प्रारंभ हुई।

शिक्षा

सन 1941 से उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाई की। वे आई.एस.सी. परीक्षा में प्रथम आये और उसके बाद कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र और गणित में बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1953 में वे कैंब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में दोबारा बी.ए. किया और अपनी कक्षा में प्रथम रहे। अमर्त्य सेन कैंब्रिज मजलिस का अध्यक्ष भी चुने गए। जब वे कैंब्रिज में पी.एच.डी. के छात्र थे उसी दौरान उन्हें नव-स्थापित जादवपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव आया। उन्होंने सन 1956-58 तक यहाँ कार्य किया। इसी दौरान सेन को ट्रिनिटी कॉलेज से एक प्रतिष्ठित फ़ेलोशिप मिली जिसने उन्हें अगले चार साल तक कुछ भी करने की स्वतंत्रता दे दी जिसके बाद अमर्त्य ने दर्शन पढ़ने का फैसला किया।

केनेथ ऐरो नाम के एक अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धांत नाम की अपनी खोज में कहा था कि व्यक्तियों की अलग-अलग पसन्द को मिलाकर समूचे समाज के लिए किसी एक संतोषजनक पसन्द का निर्धारण करना सम्भव नहीं हैं। प्रो. सेन ने गणितीय आधार यह सिद्ध किया है कि समाज इस तरह के नतीजों के असर को कम करने के उपाय ढूँढ सकता है।

शोध कार्य

सन 1960 और 1970 के दशक में अमर्त्य सेन ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से 'सोशल चॉइस' के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ ऐरो ने इस सिद्धांत को अपने कार्यों के माध्यम से पहचान दिलाया था। सन 1981 में उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'पावर्टी एंड फेमिंस: ऐन एस्से ऑन एनटाइटेलमेंट एंड डीप्राइवेशन' प्रकाशित की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि अकाल सिर्फ भोजन की कमी से नहीं बल्कि खाद्यानों के वितरण में असमानता के कारण भी होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि 'सन 1943 का बंगाल अकाल' अप्रत्याशित शहरी विकास (जिसने वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी) के कारण हुआ। इसके कारण लाखों ग्रामीण मजदूर भूखमरी का शिकार हुए क्योंकि उनकी मजदूरी और वस्तुओं के कीमतों में भीषण असमानता थी। अकाल के कारणों पर उनके महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा 'डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स' के क्षेत्र में अमर्त्य सेन के कार्यों ने 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' के 'मानव विकास रिपोर्ट' के प्रतिपादन में विशेष प्रभाव डाला। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' की 'मानव विकास रिपोर्ट' एक वार्षिक रिपोर्ट है जो विभिन प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सूचकों के आधार पर विश्व के देशों को रैंक (स्थान) प्रदान करती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और सामाजिक सूचकों में अमर्त्य सेन का सबसे महत्वपूर्ण और क्रन्तिकारी योगदान है 'कैपबिलिटी' का सिद्धांत, जो उन्होंने अपने लेख 'इक्वलिटी ऑफ़ व्हाट' में प्रतिपादित किया।

अमर्त्य सेन ने अपने लेखों और शोध के माध्यम से गरीबी मापने के ऐसे तरीके विकसित किये जिससे गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपयोगी जानकारी उत्पन्न किये गए। उदहारण के तौर पर, असमानता पर उनके सिद्धांत ने इस बात की व्याख्या की कि भारत और चीन में महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की संख्या ज्यादा क्यों है जबकि पश्चिमी और दूसरे कुछ गरीब देशों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कुछ ज्यादा और मृत्यु दर भी कम है। सेन के अनुसार भारत और चीन जैसे देशों में महिलाओं की

संख्या इसलिए कम है क्योंकि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है और लिंग के आधार पर भ्रूण हत्या भी होती है।

सेन के अनुसार शिक्षा और जन चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। सन 2009 में अमर्त्य सेन ने 'द आईडिया ऑफ़ जस्टिस' नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसके द्वारा उन्होंने अपना 'न्याय का सिद्धांत' प्रतिपादित किया।

उन्होंने कहा- "अर्थशास्त्र का सम्बन्ध समाज के गरीब और उपेक्षित लोगों के सुधार से है।" उनके अर्थशास्त्र के ये नियम आगे चलकर 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' के रूप में विख्यात हुए। उन्हें इसी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसी प्रकार, अकाट्य तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया कि वर्ष 1943 का प. बंगाल का अकाल प्राकृतिक नहीं, बल्कि मानव निर्मित आपदा थी। तत्कालीन सरकार ने जन-आवश्यकताओं की उपेक्षा कर समस्त संसाधनों को विश्वयुद्ध में झोंक दिया था। इधर लोग दम तोड़ रहे थे, उधर सरकार युद्ध में मित्र सेनाओं की विजय की कामना करने में लगी थी।

अमर्त्य सेन के अर्थ दर्शन की यह विशेषता है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को कोरी बौद्धिकता के दायरे से उसे मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने अर्थशास्त्र को निष्ठुर कष्टों के जाल से मुक्ति दिलाकर उसे अधिकाधिक मानवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की है।

उन्होंने अर्थशास्त्र को गणित से अधिक दर्शनशास्त्र के नजरिये से देखा है, इसलिए वे अर्थशास्त्र के उद्धार के लिए वैसा कोई रास्ता नहीं सुझाते, जो एडम स्मिथ और रिकार्डो, जैसे अर्थशास्त्रियों की परिपाटी बन चुका है। अमर्त्य सेन से पहले के अर्थशास्त्री पूँजी, श्रम, निवेश, शेयर बाजार, वित्तीय घाटा, मुद्रास्फीति, विकास दर, सम्बन्धी आँकड़ों की व्याख्या में ही उलझे थे।

आजकल मुक्त अर्थव्यवस्था और आर्थिक उदारीकरण के सिद्धान्त को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। अमर्त्य सेन आर्थिक भूमण्डलीकरण के सिद्धान्त की उपयोगिता को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका मानना है कि मानव संसाधनों के विकास के बिना भूमण्डलीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

उन्होंने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित कई मौलिक सिद्धान्त भी दिए। डॉ. सेन के 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' के क्षेत्र में किए गए कार्यों की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्हें पुरस्कार देने वाली समिति ने उनके बारे में टिप्पणी की थी- "प्रोफेसर सेन ने 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' की बुनियादी समस्याओं के शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।" डॉ. सेन की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1999 में 'भारत रत्न' देकर सम्मानित किया। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल को आगे बढ़ाने के लिए की गई विशिष्ट सेवा और जन-सेवा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार विश्वप्रसिद्ध प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार में उनका सहयोग ले रही है। उन्हें विश्व के कई विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधियाँ देकर सम्मानित किया है। डॉ. अमर्त्य सेन ने 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र' में महिलाओं और वंचित वर्ग के कल्याण का स्वप्न देखा है।

आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया जोरों पर है, इस सन्दर्भ में उनका मत है कि विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही वैश्वीकरण की दिशा में कदम उठाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वे इन दोनों देशों के वैश्वीकरण की अन्धी दौड़ में शामिल होने के पक्षधर नहीं हैं।

इस समय वे अमेरिका के हॉवर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनका अर्थचिन्तन ही नहीं, उनका सम्पूर्ण जीवन भी मानव समुदाय के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। अपने देश के आर्थिक विकास के लिए अपने प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए वे हर वर्ष यहाँ आते हैं।

अर्थचिंतन

अर्थशास्त्र को सामान्यतः एक शुष्क और उबाऊ विषय माना जाता है. यह धारणा आम है कि अर्थशास्त्र मनुष्य, पूंजी एवं विकास के अंतःसंबंधों की समीक्षा नितांत बौद्धिक तकनीक के आधार पर करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार

अर्थ-विनियोजन की कुशलता, कम पूंजीनिवेश द्वारा अधिकतम लाभ कमाने की अवधारणा में निहित रहती है. हर पूंजीपति सौ रूपये लगाकर हजार रूपये कमाने का सपना देखता है. मगर यह शोषण के बिना संभव नहीं. अर्थशास्त्र की प्रायः सभी स्थापनाएं, सिद्धांत, नियम आदि आंकड़ों पर निर्भर करते हैं. आंकड़ों की विश्वसनीयता का स्तर ही अर्थशास्त्रीय नियमों की विश्वसनीयता का स्तर ही अर्थशास्त्रीय नियमों की शुद्धता वह प्रमाणिकता को निर्धारित करता है. अर्थशास्त्री अपनी बौद्धिक क्षमता, लगन व परिस्थितियों के अनुसार आंकड़ों का संचयन करता है. उन आंकड़ों का विश्लेषण जिन सामान्य निष्कर्षों की ओर ले जाता है, वही कालांतर में सिद्धांतों का रूप ग्रहण कर लेते हैं. आंकड़ों के विश्लेषण में गणितीय औसत या माध्य की सहायता ली जाती है. गणितीय माध्य एक तरह से बीच का रास्ता है, जो अलग दिखने वाले आंकडों के बीच सामान्यता की स्थिति को दर्शाता है, परंतु सामान्य धारणा के विपरीत आंकड़ों का खेल कभी-कभी हमें यथार्थ स्थिति से दूर भी ले जाता है. तब प्राप्त परिणाम विचित्र-सी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं.

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन के योगदान को समझने के लिए आंकड़ों के इस मायाजाल को समझना भी बेहद जरूरी है. अपने समकालीन अर्थशास्त्रियों से एकदम विपरीत वे आंकड़ों बचकर निकलने की कोशिश में रहते हैं. उनके अर्थदर्शन की मुख्य विशेषता भी यही है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को निष्ठुर आंकड़ों के जाल से मुक्ति दिलाकर उसे अधिकाधिक मानवीय स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की है. अर्थशास्त्र को गणित से अधिक दर्शनशास्त्र के नजरिये से देखा है उन्होंने. इसलिए वे अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए वैसा कोई रास्ता नहीं सुझाते जो एडम स्मिथ और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों की परिपाटी बन चुका है. वे मानते हैं आंकड़ों की बाजीगरी का लाभ पूंजीपति तो उठा सकता है. इसलिए एडम स्मिथ और रिकार्डो के सिद्धांत पर चलने से पूंजीवाद ही फला-फूला है. बहुत जरूरी है कि आर्थिक मुद्दों पर भी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए, ताकि आमआदमी की समस्याएं चिंतन के दायरे में आ सकें. अमर्त्य सेन से पहले के अर्थशास्त्री पूंजी, श्रम, निवेश, शेयरबाजार, वित्तीय घाटा, मुद्रास्फीति, उद्योग और विकासदर संबंधी आंकड़ों की व्याख्या में ही उलझे थे. मार्क्स तो इस आधार पर वर्गसंघर्ष का ऐलान भी करा चुका था. वे मार्क्स को गलत नहीं मानते. लेकिन उनका मानना है कि साम्यवाद भी अंततः तानाशाही की व्यवस्था है. अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें तानाशाही श्रमिक-संगठनों की ओर से सौंपी जाती है. गरीब आदमी के लिए न्याय तभी संभव है, जब उसके लिए सोचने वाली सरकार हो. इसमें भले ही सरकार का भी अपना स्वार्थ क्यों न हो. सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक सरकारें जनता की अधिक समय तक उपेक्षा नहीं कर सकतीं. आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात के लिए अमर्त्य सेन के ऋणी हो सकते हैं कि उन्हेंने उन्हें भूख, गरीबी, अकाल, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता जैसे उपेक्षित मानवीय विषयों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया. आम नागरिक की सत्ता और विवेक में भरोसा जताया. उन्होंने स्वयं भी इस क्षेत्र में काफी कार्य किया. अपनी पुस्तकों एवं आलेखों में उन्होंने इन विषयों पर मानव-कल्याण से जुड़ी ऐसी दुर्लभ शोध-सामग्री दी है जिसे उससे पहले अर्थशास्त्र से बाहर समझा जाता था.

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देने की भी कोई हर्ज नहीं है कि प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अमर्त्य सेन ने भी उन्हीं सांख्यिकीय उपादानों का सहारा लिया है जिन्हें उनके पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री उपयोग करते रहे हैं, लेकिन निष्कर्षों तक पहुँचने की प्रक्रिया में उन्होंने मानवीय इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि इन मुद्दों को निरंतर अपने अध्ययन की केंद्रीय सामग्री बनाए रखा. अमर्त्य सेन के अर्थदर्शन की यही विशेषता उन्हें मानववादी अर्थशास्त्री की पहचान देती है. अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में निरी-बौद्धिकता के स्थान पर संवेदनायुकत बौद्धिकता क्यों आवश्यक है, यह जानने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे.

एक कारखाने की कल्पना करते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक कुल सौ कर्मचारी हैं. सबसे ऊपर के स्तर पर मालिक, प्रबंधक, निदेशक आदि आते हैं. जिनकी संख्या दस है. मान लें कि कारखाना इनमें से प्रत्येक पर वेतनादि के रूप में, पचास हजार रुपए खर्च करता है. कारखाने के मध्यस्तर के कर्मचारियों की संख्या बीस है. इस वर्ग में सुपरवाइजर, फोरमेन, मिस्त्री आदि शामिल हैं. मान लें कि कारखाना इनमें से हर एक पर पंद्रह हजार रुपये मासिक खर्च करता है. शेष सत्तर कर्मचारियों में छोटे तकनीशियन, मशीन,

ओपरेटर, सहायक आदि शामिल हैं, जिन्हें हर महीने तीन हजार रुपए औसत वेतन प्राप्त होता है. उल्लेखनीय है कि उदाहरण के रूप में हमने यहाँ जो वेतन मान लिए हैं, वे वास्तविकता के काफी निकट हैं. पूँजीवादी संरचना के अंतर्गत कारखानों की वेतन व्यवस्था आमतौर पर ऐसी ही होती है. यहाँ आंकड़ों की विश्वसनीयता भी असंदिग्ध है, क्योंकि कारखाना वेतन की मद में जो धनराशि खर्च करता है उसका रिकार्ड उपलब्ध है. अब यदि हम कारखाने की कुल वेतन-राशि की गणना करें, तो वह दस लाख दस हजार रुपए बैठती है. इस आधार पर कारखाने के एक कर्मचारी का औसत वेतन दस हजार सौ रुपये आता है. यह वेतनमान न तो उच्च-वर्ग पर तैनात अधिकारियों के वेतन को दर्शाता है, न यह निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन का प्रतिनिधित्व करता है. वस्तुतः औसत वेतनमान कर्मिक-वर्ग के वेतन से साढ़े तीन गुना अधिक व मालिक-वर्ग के वेतन का लगभग पांचवा हिस्सा है. प्राप्त परिणाम मध्य-स्तर पर तैनात कर्मचारियों के संगत बैठाने की कोशिश करते हैं जिनकी संख्या मात्र बीस प्रतिशत है.

अमर्त्य सेन ने निर्धनता को बहुत करीब से देखा था. 1943 में बंगाल में पड़े भयंकर दुर्भिक्ष की स्मृति उनके मानस में सुरक्षित थी. ढाका तो वैसे ही गरीबी का मारा हुआ शहर था. किसी जमाने में दुनिया-भर को रेशमी वस्त्रों की आपूर्ति करने वाले कारीगर मशीनों के आगमन के बाद से बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे. जिस काम को पीढ़ियों से संभालते आए थे, जिससे उनकी पहचान थी, उनके बच्चे उसी काम से दम तोड़ रहे थे. गरीबी की मार से वहाँ उन्होंने लोगों को एक-एक रोटी की खातिर तड़फते, भूख से फड़फड़ाते, दम तोड़ते, बूढ़े-बच्चों, स्त्री-पुरुषों को देखा था. अर्थशास्त्र को अध्ययन का विषय चुनने के पीछे उनका उद्देश्य गरीबी से जूझना ही था. इसलिए अर्थशास्त्रीय विवेचना के दौरान उन्होंने समाज के निम्नतर व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक जरूरतों को समझने व गरीबी के कारणों की समीक्षा करने पर पूरा ध्यान दिया. उन्होंने समाज में आय-वितरण की स्थिति को दर्शाने के लिए निर्धनता सूचकांक विकसित किया. इसके लिए आय-वितरण, आय में असमानता और विभिन्न आय वितरणों में समाज की क्रय क्षमता के संबंधों की सूक्ष्म, व्याख्या करते हुए, अमर्त्य सेन ने निर्धनता सूचकांक व अन्य कल्याण संकेतकों को परिभाषित किया. यह बड़ा काम था. कल्याण सूचकांकों की आवश्यकता विभिन्न देशों में चल रही कल्याण वितरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन अथवा अपने ही देश में कल्याण वितरण की व्यवस्था की समीक्षा एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए पड़ती है. इससे निर्धनता के लक्षणों को समझना और उसकी वास्तविकता की तह में जाना आसान हो गया. इससे पहले, जैसा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, निर्धनता की स्थिति को समझने के लिए जनसंख्या के उस हिस्से को आधार बनाया जाता था जिसकी आमदनी पूर्वनिर्धारित आय अर्थात गरीबी की कथित रेखा से कम होती थी. इस व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि समूह की सकल आय बढ़ जाने के बाद भी निर्धनता की वास्तविक स्थिति में सुधार होना, अवश्यंभावी नहीं होता. उपर्युक्त उदाहरण में ही यदि औसत वेतन दुगुना कर दिया तो भी आवश्यक नहीं है कि कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन दुगुना हो जाएगा। क्योंकि समूह की कुल आमदनी बढ़ने का अभिप्रायः निम्नतर सदस्य की आमदनी बढ़ना नहीं होता.

उनकी दृढ़ मान्यता है कि कल्याण की स्थिति तक पहुंचने के लिए समता-महत्त्वपूर्ण नहीं होती, महत्व हमेशा उन गतिविधियों का होता है जिनके लिए समता की आवश्यकता पड़ती है. लोकतंत्र अपने नागरिकों के विकास के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराने का पक्षधर होता है, लेकिन अवसर ही न हों तो? पुनश्चः समान आय का महत्त्व उसके द्वारा सृजित अवसरों के कारण होता है. अमर्त्य सेन ने इन अवसरों को 'क्षमताएं' भी कहा है. इन अवसरों (या क्षमताओं) की आवश्यकता व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समानता तथा संसाधनों के वितरण की स्थिति पर भी निर्भर करती है.

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन का इतना ही मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण योगदान अकाल संबंधी अध्ययन के लिए है. इस बारे में अमर्त्य सेन से पहले सामान्य धारणा यह थी कि अकाल खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण होते हैं, परन्तु दुनिया में पड़े अकालों के विस्तृत एवं तार्किक विश्लेषण के आधार पर अमर्त्य सेन ने बताया कि अकाल का मुख्य कारण मूलतः वे सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के क्रय शक्ति का ह्रास करती हैं. अपने अकाट्य तर्कों से उन्होंने स्पष्ट किया

कि 1943 का पश्चिमी बंगाल का अकाल पूर्णतः प्राकृतिक आपदा नहीं थी. वह मानव-निर्मित आपदा थी. तत्कालीन सरकार ने जनावश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए अपने समस्त संसाधनों को विश्वयुद्ध में विभिन्न मोर्चों पर लड़ रही विदेशी सेना के ऊपर झोंक दिया था. जिस समय लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, सरकार विश्वयुद्ध में मित्र सेनाओं की विजय-कामना कर रही थी. भारत और यहां के नागरिक गोया युद्ध के अलावा किसी और काम के न थे. दूसरे पश्चिमी बंगाल उन दिनों स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ था. उन पर अपना गुस्सा उतारते हुए अंग्रेज सरकार ने स्थानीय जनता के हितों की भी अनदेखी की. उन दिनों देश के बाकी हिस्सों में अनाज उत्पादन सामान्य रहा था. बंगाल में ही जमींदारों और साहूकारों के गोदाम भरे पड़े थे. सरकार यदि प्रयत्न करती तो जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न की आसानी से आपूर्ति कर सकती थी. इससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हजारों लोगों को बचाया जा सकता था. मगर सरकार अपने स्वार्थ से एक भी कदम पीछे न हटी. परिणाम यह हुआ कि लाखों लोग अकाल के कारण मौत के आगोश में चले गए. अगर उस समय देश में लोकतंत्र होता तो, जनता और उसके नुमाइंदे संसद में अकालपीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाकर सरकार की नाक में दम कर सकते थे. लेकिन साम्राज्यवादी सरकार के आगे आम भारतीय तो दूर, उसके नेताओं की कोई सुनवाई न थी.

भारत के अतिरिक्त अमर्त्य सेन ने बांग्लादेश, इथियोपिया, कोरिया और सहारा क्षेत्रों में पड़े अकालों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का विशद् एवं तुलनात्मक अध्ययन भी किया. उन्होंने सिद्ध किया कि बांग्लादेश में पड़े अकाल का कारण भी खाद्यानों की कमी नहीं थी उन दिनों बांग्लादेश को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिससे किसानों की फसल तबाह हो गई. बाढ़ में घिरा होने के कारण अगले मौसम की फसलों की बुवाई भी रुक गई, जिससे खेतिहर मजदूरों के रोजगार अवसरों में अप्रत्याशित और भारी गिरावट आई. रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण लोगों की आमदनी तेजी से गिरी, जिससे उनकी क्रय शक्ति समाप्त हो गई. लोग भूख से मरने लगे. परिणामस्वरूप वहां भी अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. अफ्रीका में पड़े अकालों या वैसी स्थितियों के कारण भी वहाँ की आर्थिक व राजनैतिक अस्थिरता एवं युद्ध की आशंकाओं में निहित हैं, जिनसे पूंजी को अनुत्पादक मदों में सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है.

अकाल-संबंधी अध्ययन के दौरान अमर्त्य सेन इस चौंकाने वाले परिणाम पर पहुंचे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो पातीं. क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह सरकारों के लिए जनसमस्याओं की अनदेखी कर पाना संभव नहीं होता. भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ आजादी के बाद कई ऐसे अवसर आए जब खाद्यान्न-उत्पादन आवश्यकता से कम रहा. कई स्थानों पर बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा. परंतु सरकार ने वितरण व्यवस्था को चुस्त बनाकर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न न होने दी.

आजकल मुक्त अर्थव्यवस्था और आर्थिक उदारीकरण के सिद्धांत को विश्व के प्रायः सभी देशों में मान्यता प्राप्त है. अधिकांश देश इसे अपना चुके हैं. जो बचे हैं वे इसे अपनाने की प्रक्रिया में हैं. चीन और रूस जैसे साम्यवादी देश भी पूंजीवाद का राग अलाप रहे हैं. अमर्त्य सेन आर्थिक भूमंडलीकरण के सिद्धांत की उपयोगिता को तो स्वीकारते हैं, परंतु उनका मानना है कि मानव संसाधनों के विकास के बिना भूमंडलीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समानता के अभाव में भूमंडलीकरण अनेक परेशानियों का जनक भी बन सकता है. विश्व-स्तर पर स्पर्धा के लिए आवश्यक है कि हम भी अपने समाज को भी वैसा ही उन्नत बनाएं. तभी वैश्विक सहभागिता पनप सकती है. भूमंडलीकरण से उनका आशय है, विकास की समरसता. उसमें जन-जन की सहभागिता. इनके अभाव में भूमंडलीकरण किस प्रकार खतरा बन सकता है, इसके लिए वे इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं. बाकी देशों की तरह इंडोनेशिया ने भी मुक्त-व्यवस्था को अपनाते हुए भूमंलडीकरण के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी. इससे वहां बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पूंजी-निवेश की बाढ़-सी आ गई. अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. समृद्धि आई, परंतु मंदी की संभावना के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने अचानक पूंजी समेटना शुरू कर दिया. इस अप्रत्याशित पूंजी-पलायन से बेरोज़गारी बढ़ी. बैंक खाली पड़ने लगे. लोग इसके लिए तैयार नहीं थे. परिणामतः देश गंभीर आर्थिक संकट में फंस गया.

अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के फलक को व्यापक बनाना चाहते हैं. उनके सामाजिक सरोकार स्पष्टतः मानवीय हैं. वे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या और कैसे संभव है कि समाज अपनी प्राथमिकताएं अपने सदस्यों की पसंद और अपेक्षाओं के अनुसार तय करे. आम सहमति के अनुसार ही श्रेष्ठ विकल्प चुना जा सकता है. उसपर किसी प्रकार के विवाद की संभावना नहीं रहती. परंतु एक सार्थक आम-सहमति के लिए समाज के विवेकीकरण की आवश्यकता पड़ती है. यह तभी संभव है, जब समाज का वौद्धिक स्तर ऊंचा हो. उसमें कम से कम आंतरिक तनाव हों. अगर किन्हीं कारणों से आमसहमति अगर न बन पाए तो क्या करें? वह कौन सा रास्ता है जब परस्पर विरोधी दिखने वाले विचारों का समन्वय कर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो सारे समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये प्रश्न साठ के दशक में ही चर्चा में आ चुके थे. कुछ अर्थशास्त्री इन पर गंभीरतापूर्वक कार्य भी कर रहे थे. 1972 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कैनेथ केरो ने विभिन्न विचारों के समन्वय और विशिष्ट पसंदों यथा मानवीय मूल्यों एवं कल्याण संसाधनों के वितरण के लिए बहुमत के विकल्प को अपनाने का सुझाव दिया. सहकारिता यह काम उनीसवीं शताब्दी के मध्याह्न में ही प्रारंभ कर चुकी थी. उसने स्वयं को पूंजीवाद के सशक्त विकल्प के रूप में खड़ा किया था. लेकिन बाद में सहकारी संस्थाओं पर भी राजनीति और बाजारवाद का रंग चढ़ने लगा. वे कर्तव्य के बजाय अधिकारों की बातें करने लगीं. नतीजा यह हुआ कि वे अपने लक्ष्य से भटकती चलीं गईं. और आजकल तो बड़े सहकारी संस्थान अपने उद्योगों के प्रबंधन के लिए वही मापदंड अपनाते हैं, जो दूसरे पूंजीवादी कारखानों में चलता है.

केरो का यह भी मानना था कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, जो सभी परिस्थितियों में खरा बना रहे. विकल्प की कसौटी के रूप में उन्होंने पांच स्वयंसिद्ध निष्कर्षों की संकल्पना की. केरो के अनुसार स्वयंसिद्ध निष्कर्ष वे हैं जो स्वयं में तर्कपूर्ण प्रतीत हों. जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार, स्वास्थ्य, शिखा व समानता आदि. जरा सोचकर देखिए. कोई समाजवादी व्यवस्था भी इसी प्रकार की कामना करती है. अमर्त्य सेन ने केरो की विचारधारा को विकसित करते हुए कहा था कि सामूहिक निर्णयों को सदैव गैर-अधिनायकवादी होना चाहिए. व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की न्यूनतम शर्त यह है कि यह नियम कुछ भाग के लोगों की व्यक्तिगत क्षेत्र से जुड़ी पसंदों को ध्यान में रखे। व्यक्तिगत और सामाजिक पसंदों के बीच तालमेल बनाए रखना बड़ा जटिल कार्य है. यह अमर्त्य सेन भी मानते हैं. व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामूहिक निर्णय के नियम के कल्याणकारी समन्वय के प्रयास में आज भी अनेक अर्थशास्त्री जुटे हुए हैं.

अमर्त्य सेन छटे दशक से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं. जिस कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसका खुलासा उन्होंने अपनी पुस्तक 'सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण' में 1970 में ही कर दिया था. मगर तब भूमंलडीकरण का नया जोश था. पूंजीवाद के इशारे पर नाचते देश किसी की सुनने को तैयार न थे. अमर्त्य सेन की स्थापनाएं अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में तो स्थान पा सकीं, मगर उन्हें सही सम्मान जिसके वे बहुत पहले से हक़दार थे, मिलने में तीन दशक लग गए. यह सब अचानक नहीं हुआ। बल्कि अनियोजित पूंजीकरण के कारण पैदा हुए असंतुलन के कारण विद्वानों को अमर्त्य सेन को सम्मानित करने के लिए बाध्य होना पड़ा. भूमंडलीकरण अभियान का अगुआ देश अमेरिका भी इस असंतुलन से अछूता नहीं रहा. 'अंतरराष्ट्रीय शोध संगठन 'यूनाइटेड फोर फेयर इकोनोमी' की 'शती की समाप्ति पर आर्थिक असमानता' शीर्षक से रिपोर्ट में दुनिया-भर की अर्थव्यवस्था को राह दिखाने का दम भरने वाले दंभी अमेरिका के खोखलेपन का उजागर किया गया है. रिपोर्ट में उल्लिखित है कि पिछले दशक में अमेरिका अर्थव्यवस्था ने जहां चंद लोगों को अरबपतियों की कतार में पहुंचाया, वहीं तीस लाख से अधिक आबादी को गरीबी को गर्त में ढकेल दिया. एक सर्वे ने बताया था कि भारत के बीस करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन बीस रुपये कम की आय पर जीवन-निर्वाह करते हैं. वेतन विसंगतियों का हाल यह है कि प्रमुख बड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारी, आम फैक्ट्री मजदूर की तुलना में 1000 गुना तक अधिक वेतन लेते हैं. 1968 के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की क्रय क्षमता 31 प्रतिशत घटी है. स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण के नाम पर आपाधापी में की गई कोशिशें के नाम पर पूंजीवाद ही थोपा गया है, जिससे कारखानेदार अमीर पर अमीर होते जा रहे, जबकि आम आदमी की गरीबी और

दुर्दशा बढ़ती ही जा रही है. साम्राज्यवाद के दौर में औपनिवेशिक देशों की पूंजी अमीर देशों की ओर खिंचती चली जाती है. पूंजीवाद के फलस्वरूप विकासशील देशों में भी अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी है. मगर वहां विकास के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है कि आमआदमी की गाढ़ी कमाई उद्योगपतियों का खजाना बढ़ाने में लगी है. लगता है कि हम अमेरिका के किसी आर्थिक उपनिवेश में जी रहे हैं.

अमर्त्य सेन के अर्थचिंतन और सहकारिता का साम्य

अमर्त्य सेन के विचार समाजवाद और उसके समानधर्मा विचार सहकारिता की भावना से काफी मेल खाते हैं. अमर्त्य सेन कल्याण सरकार के रूप में जिस व्यवस्था की बात रखते हैं, वही समाजवाद और सहकारिता का सपना है. उल्लेखनीय है कि किसी भी नई खोज अथवा विचार की महत्ता समाज के प्रति उसकी उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है. उससे संबंधित सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांत अथवा विचार इस निर्णय की कसौटी बनते हैं. तुलनात्मक आधार पर अधिक उपयोगी पाए जाने पर ही नए विचार को सार्वजनिक स्वीकृति मिल पाती है. तथापि यह आवश्यक नहीं है कि नया विचार सर्वथा मौलिक एवं परंपरा से हटकर हो! कभी-कभी पुराने और अप्रचलित सिद्धांत जो विभिन्न कारणों से अप्रासंगिक करार दे दिए जाते हैं, की युगानुकूल एवं तार्किक पुनःव्याख्या भी नए-से लगने वाले सिद्धांत को जन्म दे देती है. इस तरह कालातीत मान लिया गया विचार भी नए सिद्धांत को जन्म दे देती है.

अमर्त्य सेन का अर्थदर्शन भी कदाचित ऐसे ही विचारों की जिन्हें विकास की दौड़ से कालातीत अप्रासंगिक, या पिछड़ा मान लिया गया या, समसामयिक एवं युगानुकूल व्याख्या है. सीधे शब्दों में कहें तो अमर्त्य सेन ने आपसी सहयोग, संसाधनों के जनतांत्रिक उपयोग, एवं उत्तरदायी जनतांत्रिक सत्ता के लक्षणों एवं जनकल्याण हेतु इनकी उपयोगिता का अर्थशास्त्रीय भाषा में विश्लेषण किया है. उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के निहितार्थ महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज व आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय से अलग नहीं हैं. इन दोनों महापुरुषों ने जिस विकेंद्रीकृत व्यवस्था की परिकल्पना की थी, और जिस आत्मनिर्भर समाज का सपना हमें दिखाया था, अमर्त्य सेन का सिद्धांत उसी की अर्थशास्त्रीय व्याख्या है. सुविज्ञ अर्थशास्त्री होने के कारण अमर्त्य सेन की व्याख्याएं और प्रस्तुतीकरण का ढंग परंपरा से हटकर है. वे अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों का लोक से निरपेक्ष रहकर विश्लेषण नहीं करते, अपितु सरकार के प्रत्येक निर्णय में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित रखना चाहते हैं. लोकतंत्र में निर्णय की प्रक्रिया लोकप्रतिनिधियों द्वारा संपन्न होती है, इसलिए वे लोकतंत्र पर जोर देते हैं. उल्लेखनीय है कि समाजवाद और सहकारिता दोनों ही विचार लोकतंत्र पर आश्रित हैं. बल्कि सहकारी समिति तो अपने आप में ही लोकतांत्रिक संगठन होता है. समूह के सदस्य आपसी विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं के सामान्यीकरण और संसाधनों के साझा उपयोग पर जोर देते हैं. अमर्त्य सेन का सामूहिक विकल्पों का सिद्धांत सहकारिता के सामूहिक विकास की अभिकल्पना का ही विस्तार है. हालांकि वे सीधे-सीधे सहकारिता का पक्ष नहीं लेते, न वे समाजवाद को आंदोलनों के रूप में आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, बल्कि वे सभी लक्ष्य जो समाजवाद और सहकारिता के माध्यम से जा सकते हैं, उन्हें कल्याण सरकार का दायित्व बताकर वे जनप्रतिनिधियों से अधिक जागरूक, समर्पित और सक्रिय बने रहने की अपेक्षा रखते हैं. वे लोक को भी जाग्रत बनाना चाहते हैं. ताकि जनप्रतिनिधियों के चयन के समय बिना किसी भेद-भाव और जातीय पूर्वाग्रह के निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर सकें. अमर्त्य सेन के अर्थचिंतन की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने जिन विचारों को अपने चिंतन का आधार बनाया है, इससे पहले उन्हें अर्थशास्त्र की विषयवस्तु मानने की परंपरा नहीं थी! उन्हांने सामूहिक विकल्पों के चुनाव पर सर्वाधिक जोर दिया हैं; इसके पीछे उनकी मंशा विकासचक्र को उस गरीब आदमी तक ले जाने की रही है, जो वर्तमान व्यवस्था में वंचित ओर बहिष्कृत है, और यदि हम गंभीरतापूर्वक सोचकर देखें तो यही समाजवाद का उद्देश्य है, यही सहकारिता आपसी मेलजोल के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है.

सामूहिक विकल्प या विकल्पों के सर्वसम्मति (अथवा कम से कम सामान्य सहमति) से चुनने की अवधारणा, सहकारिता की भावना के काफी निकट है. सहकारिता सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों को, सीमित संसाधनों द्वारा, फलीभूत करने के लिए किए गए प्रयासों का नाम है, जिनमें समूह के प्रत्येक सदस्य की यथा सामथ्र्य साझेदारी होती है. जहां संसाधन सीमित मात्रा संख्या में हों. संसाधनों

की प्रचुर उपलब्धता की स्थिति में सहकारिता की जरूरत ही नहीं पड़ती. यद्यपि ऐसा बहुत कम होता पाता है. समाज में लोगों की महत्वाकांक्षाएं जितनी तेजी से बढ़ती हैं, संसाधनों का सृजन उतनी तीव्रता के साथ नहीं हो पाता. अतः सहकारिता की उपयोगिता हमेशा बनी रहती है. सहकारिता का दूसरा और महत्त्वपूर्ण लक्षण है सहकार अर्थात समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ संगठित प्रयास करने का संकल्प. अमर्त्य सेन जब कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विवेचना करते हैं; तब उनका इशारा निसंदेह विकासशील समाजों की ओर होता है. जहाँ गरीबी है, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, धर्म और जाति के आधार पर भारी भेदभाव हैं. संसाधनों का असमान बंटवारा और विकास के अवसरों में धांधलेबाजी है. इस प्रकार कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सहकारिता की आवश्यकता लगभग एक जैसे, विकासमान या विकास की परंपरा से कटे हुए, समाजों में पड़ती है. किसी समूह द्वारा विकास की दिशा में किए जा रहे संगठित प्रयासों में सफलता के लिए उसके सदस्यों की अधिकतम भागीदारी एवं समूह के लक्ष्यों के प्रति सर्वसहमति अथवा आमसहमति होनी आवश्यक है. साथ ही जरूरी है नेतृत्व के प्रति आस्था! समूह के साथियों के प्रति विश्वास और अपनत्व की भावना. इनके अभाव में समूह के प्रयासों के प्रति असदस्यों का ईमानदार रह पाना संभव नहीं है, जिन्हें नेतृत्व तथा सामूहिक लक्ष्यों के प्रति अनास्था है; या जो मानते हैं कि नेतृत्व द्वारा उनके हितों की निरंतर उपेक्षा की जा रही हैं, वे कालांतर में संगठन से दूर जाने लगते हैं. जिससे सहकारिता और सहविकास का लक्ष्य अधूरा रह जाता है. अभिप्रायः यह है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अमर्त्य सेन जैसे कल्याण राज्य की विवेचना अपनी व्याख्याओं में करते हैं, सहकारी समूह के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए वैसे ही कल्याणकारी नेतृत्व की जरूरत पड़ती है.

अमर्त्य सेन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की विवेचना में राज्य नामक सत्ता का न केवल उल्लेख करते हैं, बल्कि उसके कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए भी नज़र आते हैं. यद्यपि राजनीतिक विश्लेषण करना उनका अभीष्ठ नहीं, तथापि कल्याणकारी गतिविधियों की व्याख्या के दौरान राज्य की उपस्थिति पर्यवेक्षक सत्ता के रूप में बनी रहती है. जबकि सहकारी समूह स्वयं अनुशासित व समर्पित मानव इकाई (या इकाइयों) द्वारा संचालित उत्प्रेरित होता है. समूह के सदस्य कर्ता होने के साथ-साथ अपने आचरण के स्वयं-पर्यवेक्षक भी होते हैं. उनका यही गुण उन्हें शेष सदस्यों से तालमेल बनाए रखने, निर्णय की प्रक्रिया के दौरान खुलकर विमर्श करने को प्रेरित करता है. उल्लेखनीय है कि के नेतृत्व की आवश्यकता सहकारी समूहों के लिए भी होती है. मगर इसके लिए जिम्मेदार, समूह की शीर्षस्थ शक्तियों का नैतिक आचरण, लक्ष्यों के प्रति उनका समर्पण भाव तथा लक्ष्यों एवं स्थितियों को समझने की उनकी बौद्धिक कुशलता ही समूह के बीच उन्हें विशिष्ठ दर्जा प्रदान करती है. इस तरह बिना कोई संवैधानिक दर्जा पाए अपनी योग्यता एवं समूह के आन्तरिक अनुशासन के बल पर ही वे शेष इकाइयों के प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक बने रहते हैं.

पत्राचार पता (Communication address):

Dr. Shaiphali Jain
Assistant Professor (Economics),
Shri Prem Prakash Memorial College of Education
(Teerthanker Mahaveer University),
Moradabad, Uttar Pradesh, India.
Email: shaiphali1980jain@gmail.com

संदर्भ ग्रन्थ सूचि:

1. Anderson, E. (2003), 'Sen, Ethics and Democracy', Feminist Economics 9(2-3), 239-261.
2. Agarwal, B., Humphries, J., and Robeyns, I., (Eds.) (2003), 'A Special Issue on Amartya Sen's Work and Ideas: A Gender Perspective', Feminist Economics, 9(2-3) (July/November).
3. Arrow, K. J. (1963 [1951]), Social Choice and Individual Values. New York: Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, John Wiley and Sons, Inc.
4. Arrow, K. J. (1995), 'A Note on Freedom and Flexibility', in K. Basu, P. K. Pattanaik and K. Suzumura (eds.), Choice, Welfare, and Development: a Festschrift in Honour of Amartya K. Sen. Oxford & New York: Clarendon Press.
5. Atkinson, A.B. (1998), The Contributions of Amartya Sen to Welfare Economics. http://www.nuff.ox.ac.uk/users/atkinson/sen1998.pdf.
6. Berlin, I. (1969), Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press. Beizt C. [1999 (1979)], Political Theory and International Relations, 2nd Edition. Princeton: Princeton University Press,.

7. Fleurbaey, M and Gaertner, W. (1996), 'Admissibility and Feasibility in Game Forms', Analyse & Kritik (18) 54-66.
8. Fleurbaey, M. and Van Hees, M. (2000), 'On Rights in Game Forms', Synthese (123), 295-326.
9. Freeman, M. D. A. (1994), Lloyd's Introduction to Jurisprudence. London: Sweet and Maxwell Ltd.
10. Gaertner, W., Pattanaik, P. K. and Suzumura K., (1992), 'Individual Rights Revisited', Economica 59: 161-77.
11. Gewirth, A. (1978), Reason and Morality. Chicago and London: University of Chicago Press.
12. Gewirth, A. (1982), Human Rights: Essays on Justification and Applications. Chicago: University of Chicago Press.
13. Gewirth, A. (1996), The Community of Rights. Chicago: University of Chicago Press.
14. Vizard, P. (2004c), 'Freedom From Severe Poverty as a Fundamental Human Right: A Positive Conception in the Kantian Framework'. Unpublished Working Paper.
15. Vizard, P. (forthcoming), Poverty and Human Rights: Sen's 'Capability Perspective' Explored. Oxford: Oxford University Press.
16. Waldron, J. (1993), Liberal Rights: Collected Papers 1981-1991. New York: Cambridge University Press.
17. Williams, B. (1987), 'The Standard of Living: Interests and Capabilities', in G. Hawthorn (ed.), The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.
18. World Bank (1998), Development and Human Rights: The Role of the World Bank. Washington: The World Bank.

1/19/2021